

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उच्च न्यायालय,  
उत्तरांचल, नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 04 अगस्त, 2006

विषय: सिविल जज(जू०डि०), रामनगर, नैनीताल के न्यायालय परिसर में कैन्टीन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1693/UHC/Admin.B/Const./2005, दिनांक 30.6.06 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल जज(जू०डि०), रामनगर, नैनीताल के न्यायालय परिसर में कैन्टीन के निर्माण हेतु रु० 4,47,000/- के आगणन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रु० 4,45,000/- (रुपये चार लाख पैतालीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 4,45,000/- (रुपये चार लाख पैतालीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
- (4) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (5) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (6) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (7) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।
- (8) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

- (9) किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय ।
- (10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशाली अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय-व्यय की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00-25-लघु निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।
- 3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-505/XXVI(5)/2006, दिनांक 25.8.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीया,

( इन्दिरा आशीष )  
सचिव ।

संख्या-25-दो(1)/XXXVI(1)/2006-71-दो/02-तददिनांक ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
  2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
  3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
  4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
  5. अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर, नैनीताल ।
  6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
  7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा में,  
( आलोक कुमार वर्मा )  
अपर सचिव ।